विश्व बैंक राजस्थान के चार शहरों के लिए 3500 करोड़ रूपए देगा

इस परियोजना में जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर व उनसे जुड़े 28 सैटेलाइट टाउन शामिल होंगे

■ **विश्व बैंक परियोजना के तहत चारों शहरी क्लस्टर में ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण और पुनर्जीवन, शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी में सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन तथा नागरिक सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य कराये जाएंगे।**

जयपुर, 21 अक्टूबर। राजस्थान के प्रमुख शहरों में सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और नगर निकायों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन राजस्थान एक्सीलरेटेड (एसयूटीआरए-सूत्रा) परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

विश्व बैंक की ओर से जारी नवीनतम दस्तावेज के अनुसार, परियोजना में कुल 32 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर तथा उनसे जुड़े 28 सैटेलाइट टाउन शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में वर्ष 2026 में अनुमानित आबादी 78 लाख से अधिक है। इसके माध्यम से शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित बनाने और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत चारों शहरी क्लस्टर में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्जीवन, शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी में सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य करवाए जाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य शहरों को अधिक सुविधाजनक और रहने योग्य बनाना, आवागमन बेहतर करना तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखते हुए विरासत क्षेत्रों के विकास को भी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन शहरों में बढ़ती गर्मी में जल संकट और बारिश के दौरान जलभराव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी काम करवाए जाएंगे।

विश्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार, परियोजना के तहत नगर निकायों के राजस्व प्रशासन में सुधार और ऋण प्रबंधन को बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जाएंगे। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों की ऋण लेने की क्षमता मजबूत करने तथा शहरी आधारभूत ढांचे के लिए निजी एवं वाणिज्यिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर रहेगा।

परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) को बनाया जायेगा। विश्व बैंक में परियोजना की तकनीकी डिजाइन की समीक्षा आगामी 10 दिसम्बर और बोर्ड का अनुमोदन 2 जुलाई 2027 तक होना संभावित है। इसमें विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से 27 करोड़ डॉलर का ऋण तथा राज्य सरकार की ओर से 11 करोड़ 57 लाख डॉलर का वित्तपोषण प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ का सिरपुर विश्व धरोहर सूची में शामिल

महासमुंद 21 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद अंतर्गत पुण्य सलिला महानदी के तट पर स्थित सिरपुर अब विश्व के मानचित्र में चमकेगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में सिरपुर को शामिल किया गया है।

सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से विख्यात रहा है तथा पाण्डुवंशी

■ **प्राचीन काल में यह श्रीपुर के नाम से जाना जाता था तथा पाण्डुवंशी शासकों के काल में यह दक्षिण कोसल की राजधानी था।**

शासकों के काल में इसे दक्षिण कोसल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त रहा है। सिरपुर की प्राचीनता का सर्वप्रथम परिचय शरभपुरीय शासक प्रवरराज तथा महासुदेवराज के ताम्रपत्र से उपलब्ध होता है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बुधवार को बताया कि जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर सिरपुर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के आधिकारिक वेबसाइट पर तीसरे क्रम पर सिरपुर को सूचीबद्ध किया गया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 57 वर्षीय, सुदीर्घ शासनकाल में यहां अनेक मंदिर, बौद्ध विहार सरोवर तथा उद्यानों का निर्माण करवाया गया।

'मेरे परिवार को ही कब तक होल्ड पर रखा जाएगा?'

राजेन्द्र राठौड़ की नाराज़गी को मुख्यमंत्री भजनलाल ने हस्तक्षेप कर शांत किया

■ **यह मामला तब उठा जब वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ की पुत्रवधु का नाम चूरू जिला परिषद के लिए फाइनल हो गया, पर उनके पुत्र पराक्रम सिंह का नाम होल्ड पर रख दिया गया।**

जयपुर, 21 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर भाजपा में टिकट वितरण की कवायद के बीच सियासी खींचतान तेज हो गई है। जिला परिषद के टिकटों पर रायशुमारी के दौरान वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ की नाराजगी सामने आने से पार्टी की अंदरूनी राजनीति गरमा गई। चूरू में बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और बहू कनिका सिंह के लिए टिकट की पैरवी कर रहे राठौड़ उस समय नाराज हो गए, जब बहू का टिकट फाइनल करने और बेटे का नाम फिलहाल होल्ड पर रखने का प्रस्ताव सामने आया। मामला बढ़ने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा।

बुधवार को भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में राठौड़ ने बेटे का टिकट रोकने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि आखिर उनके परिवार के मामले में ही ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बेटे का नाम वहां भी होल्ड पर रखा गया था। आखिर कब तक ऐसा किया जाएगा?

राठौड़ ने संगठन के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की चुनावी परिस्थितियों और जीत की रणनीति की जानकारी है। उन्होंने अन्य जगहों पर एक ही परिवार के सदस्यों को कई टिकट दिए जाने का हवाला देते हुए, अपने परिवार के मामले में अलग रवैया अपनाने पर सवाल उठाए। नाराजगी के दौरान वे बैठक छोड़कर जाने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तक्षेप कर उन्हें शांत कराया और उनकी राय को महत्व देने का भरोसा दिलाया।

टिकटों को लेकर जारी खींचतान के बीच, चूरू में राजेन्द्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने जिला परिषद के वार्ड 39 और बहू कनिका सिंह ने वार्ड 23 से नामांकन दाखिल किया। दोनों के नामांकन के बाद पार्टी के आधिकारिक टिकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा मुख्यालय में गुरुवार सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक में 13 जिलों के प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी की जाएगी।

इनमें ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल-तिजारा, बालोतरा, बारां और बूंदी जिले शामिल हैं।

भरतपुर, डीग, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों के प्रत्याशियों के चयन के लिए 22 अक्टूबर को रायशुमारी होगी।

ब्यावर जिला परिषद के वार्ड 13 में भी टिकट को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यहां दो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने अपने परिजनों के लिए टिकट की दावेदारी की थी। इनमें से एक अधिकारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की एफआईआर सामने आने के बाद संगठन ने फिलहाल इस सीट पर निर्णय टाल दिया।

ऐसे में, तीसरे चरण के टिकट वितरण को लेकर भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठकों पर सबकी नजरें रहेंगी।

जब 29 जुलाई को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में अपना पक्ष रखा।

विज्ञप्ति में कहा गया, कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग की किसी नीतिगत विषय-वस्तु या आईटी विभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। संबंधित अधिकारी द्वारा जारी कार्य-आवंटन आदेशों को दोनों चुनाव आयुक्तों के निर्देश के बाद वास्तव में लागू नहीं किया गया था। आईटी विभाग पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी कभी हटाई ही नहीं गई थी।"

आरटीआई से क्या पुष्टि होती है?

आरटीआई के जवाब से इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पत्रों की विषय-वस्तु का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे विवाद में, जिसमें अब तक ज्यादातर जानकारी लीक और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सामने आई है, यह पहला आधिकारिक दस्तावेजी प्रमाण है।

इससे पुष्टि होती है कि दोनों पत्र मौजूद हैं, वे कब प्राप्त हुए और कैबिनेट सचिव का जवाब आगे कहां भेजा गया।

एप्सटीन फाइल्स के फोटो मीडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डिजिटल विषयों पर चर्चा से संबंधित थीं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था और एपस्टीन के अपराधों या उसके द्वीप से उनका कोई संबंध नहीं था।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया, "क्या हरदीप पुरी ने यह नहीं कहा था कि उन्होंने एपस्टीन से कभी भी अकेले (वन टू वन) मुलाकात नहीं की?" तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा, "लगता है कि इन दोनों तस्वीरों में बाकी प्रतिनिधि मेज के नीचे छिपे हुए थे।" उन्होंने पुरी से कैबिनेट की बैठकों में शामिल होना बंद करने की मांग भी की।

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने तस्वीरों को बेहद गंभीर आरोपों की पुष्टि करने वाला बताते हुए, मुलाकातों में हुई बातचीत का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने सवाल किया कि पुरी किसका संदेश लेकर जा रहे थे, क्या वह संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश था? उन्होंने कहा, यह तो "शुरुआत" है।

कांग्रेस नेताओं के.सी. वेणुगोपाल और पवन खेड़ा सहित, अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी की आलोचना करते हुए इसे "आपराधिक उदासीनता" बताया और एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। कुछ नेताओं ने इस विवाद को एपस्टीन के साथ कथित तौर पर हुए अधिक व्यापक ईमेल आदान-प्रदान के दावों से भी जोड़ा।

पुरी के कार्यालय ने जवाब दिया कि मंत्री ने कभी यह दावा नहीं किया था कि वे एपस्टीन से अकेले कभी नहीं मिले। कार्यालय के अनुसार, फरवरी में दिए गए बयान में केवल यह बताया गया था कि परिचय कैसे हुआ (रोड-लार्सन के जरिए) और पहली मुलाकात एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रुप में हुई थी। कार्यालय ने कहा कि तस्वीरों में मेज के आस-पास काम से जुड़ी बैठक दिखाई दे रही है, जिस पर कुछ नोट्स और दस्तावेज मौजूद हैं। मंत्री को इस खास मुलाकात का स्पष्ट स्मरण नहीं है और वे यह भी निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि तस्वीरें लिए जाने से पहले या बाद में वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं।

पुरी के कार्यालय ने फिर दोहराया कि मंत्री कभी एपस्टीन के द्वीप पर नहीं गए थे और एपस्टीन के साथ उनका कोई सार्थक व्यक्तिगत संबंध या उसके अपराधों से कोई जुड़ाव नहीं था।

तमाम आरोपों के बावजूद, पुरी पेट्रोलियम मंत्री के पद पर बने हुए हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए भाजपा द्वारा उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के फैसले ने इन अटकलों को हवा दी है कि मंत्रिमंडल के अगले फेरबदल में उन्हें हटाया जा सकता है।

फ्रांस से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेरिस गए थे और ये सब उन्होंने केन्द्र सरकार के एनओसी न दिए जाने की चुनौती के बाद किया था।

सूत्रों के मुताबिक, भगवंत मान और उनके स्टाफ पर 50 हजार की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री मान के साथ उनका स्टाफ था, उनके भी सामान की चेकिंग की गई थी। लेकिन चेकिंग के दौरान कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं की गई थीं, लिहाजा उस पर ड्यूटी लगी है। भगवंत मान और उनका स्टाफ सामान को डिक्लेयर किए बिना ग्रीन चैनल से जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया था।

लिखित माफीनामे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा सकता है। सही जमानती पेश नहीं करने पर तीसरी बार भी इन्हें जेल भेजा जा सकता है।

राहुल गांधी ने आईएएस कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों से मुलाकात की

इसके पहले भाजपा ने एक वीडियो साझा कर राहुल गांधी के वियतनाम जाने पर सवाल उठाये थे

■ **राजनीतिक क्षेत्रों में राहुल गांधी के वियतनाम जाने की आलोचनात्मक चर्चा के बीच उनका कोचिंग विद्यार्थियों से बातचीत का वीडियो कांग्रेस की ओर से अधिकारिक रुप से शेयर किया गया।**

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को यहां विजन आईएएस कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर होने की चर्चा है। इस मुलाकात के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं।

कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया गया कि विद्यार्थियों ने संस्थान में पढ़ाई, मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता में गिरावट तथा फीस वापसी की मांग पर प्रबंधन की ओर से जवाब नहीं मिलने की शिकायत की।

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा कि विद्यार्थियों ने शिक्षण की गुणवत्ता, मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री के स्तर में तेज गिरावट को लेकर गंभीर चिंता जताई। कांग्रेस के मुताबिक, विद्यार्थियों ने बताया कि फीस वापस करने की उनकी मांग पर संस्थान का प्रबंधन जवाब नहीं दे रहा है।

इससे पहले, भाजपा ने सोमवार को एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया था कि राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं। भाजपा ने इस वीडियो के साथ तंज कसते हुए लिखा था कि झूठ फैलाते-फैलाते थकने के बाद वे कुछ दिन घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो में राहुल एक हवाई जहाज में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मंगलवार को शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत का एक वीडियो साझा किया था। इसमें राउत कह रहे हैं कि राहुल वियतनाम गए हैं, उनके आने के बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को साझा कर सवाल किया गया था कि राहुल वियतनाम में किससे मिलने वाले हैं? देश की सीमाओं के बाहर ऐसी कौन-सी प्लानिंग हो रही है? उनके भारत लौटने के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा? पोस्ट में कहा गया था कि आखिर संजय राउत ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं?

पाकिस्तान के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पंजाब के सिख श्रद्धालुओं के 1,828 पासपोर्ट, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 557, उत्तराखंड की सिख संगतों के 254 और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के 150 पासपोर्ट जमा करवाए गए हैं। झारखंड से 12 और गुजरात से दो श्रद्धालुओं के पासपोर्ट जमा करवाए गए हैं। अब पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मिलने के बाद, जत्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर को दस दिवसीय धार्मिक यात्रा के लिए रवाना होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में माथा टेकना और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना है।

अभी अधरझूल में है, अमेरिका व ईरान के बीच शांति समझौता

■ **दोनों देश अधिकारिक रूप से समझौता अटकने की बात करते हैं, पर अप्रत्यक्ष वार्ता जारी है।**

वाशिंगटन (अमेरिका)/तेहरान, 21 अक्टूबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जब तक तेहरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़) में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं करता, तब तक उस पर आर्थिक दबाव बना रहेगा। इस पर ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि जब तक वाशिंगटन, तेहरान की शर्तें नहीं मान लेता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और कतर के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो और अराघची ने अपने-अपने देश के मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। इस बीच अमेरिकी रक्षामंत्री पीट हेगसेथ का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वाशिंगटन, ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न आएं।" ईरान का यह भी कहना है कि उसका संवर्धित यूरेनियम देश के भीतर ही रहेगा। उसने लगभग 400 किलोग्राम परमाणु सामग्री को रूस की कस्टडी में सौंपने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए तेहरान के दौरे पर हैं।

सर्दी आने से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपाय अपनाए हैं। हमारे प्रयासों में जनता की भागीदारी की अहम भूमिका रही है।"

सिरसा ने कहा कि "प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 11 सूत्री कार्ययोजना लागू की जा रही है, जिसमें केन्द्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करने और प्रदूषण के स्थानीय स्त्रोतों की पहचान करने पर है।"

शिल्पकार एथिराज का निधन

■ **प्रधानमंत्री ने एथिराज को पूर्व प्रधानमंत्री नेहरु को दिये गये ऐतिहासिक सेंगोल के निर्माण के लिये याद किया।**

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक सेंगोल के निर्माण में योगदान देने वाले वुम्मिडी एथिराज के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एथिराज को, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट किए गए ऐतिहासिक सेंगोल (स्वर्ण रचित राजदंड) के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक संदेश में कहा कि तमिलनाडु के प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले एथिराज का जीवन और शिल्पकला भारत की गौरवशाली परंपराओं तथा देश की यात्रा के बीच एक उल्लेखनीय संबंध को दर्शाते हैं। उन्होंने एथिराज के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मोदी ने कहा कि वर्ष 2023 में नए संसद भवन में सेंगोल को प्रमुख स्थान देने के दौरान उन्हें एथिराज से मिलने और देश तथा संस्कृति के लिए उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर मिला था। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर इस ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि एथिराज के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है।

वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग के लिए अंबानी से वार्ता करेंगे रुबियो

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रुबियो जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी का दौरा करने आए हैं

■ **रुबियो का प्रस्ताव है कि अंबानी को वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाना चाहिए और रुसी तेल की खरीद कम कर देनी चाहिए।**

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो बुधवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने उनका स्वागत किया। रुबियो ने यहां रिलायंस की तेल रिफाइनरी का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने वंतारा और कंपनी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा कारोबार बढ़ाना चाहता है और वहां डीजल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं।

दौरे से जुड़े लोगों के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बेटी ईशा व बेटे अनंत ने रुबियो का स्वागत किया।

जामनगर पहुंचने से एक दिन पहले रुबियो ने भारत को कच्चे तेल की रिफाइनिंग के मामले में महाशक्ति बताया था। उन्होंने भारत से वेनेजुएला के कच्चे तेल की प्रोसेसिंग बढ़ाने की अपील की। जानकारों के मुताबिक, अमेरिका रिलायंस की विशाल रिफाइनिंग क्षमता का इस्तेमाल करके ऊर्जा कारोबार को मजबूत करना चाहता है। रुबियो ने नेटवर्क18 से बातचीत में कहा कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध से आने वाले कच्चे तेल की रिफाइनिंग के लिए रिलायंस के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है।

असल में अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल (क्रूड) के लिए नए बाजार तलाश रहा है। अमेरिका भारत पर वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए जोर दे रहा है।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो ने कहा कि वह रिलायंस के साथ वेनेजुएला के तेल की प्रोसेसिंग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे वेनेजुएला में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, भारत ग्लोबल तेल सप्लाई को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा, उनके पास भारी कच्चे तेल (हेवी क्रूड) को रिफाइन करने की क्षमता है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे वेनेजुएला से और अधिक तेल आएगा, वे ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। रुबियो ने भारत को रिफाइनिंग सुपरपावर करार दिया।

'आतंकवाद विरोधी मिशन का लाइव कवरेज बंद करें'

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए बुधवार को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे आतंकवाद-रोधी अभियानों की लाइव कवरेज से बचें, भड़काऊ बहस और राष्ट्रविरोधी सामग्री न दिखाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल में सावधानी बरतें।

मंत्रालय ने एडवाइज़री में सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि उनकी अंतर-विभागीय समिति ने पाया है कि चैनलों पर प्रसारित खबरें और दृश्य संहिता के अनुरूप नहीं हैं और एक ही तरह के दृश्य बार-बार दिखाए जा रहे हैं।

एक्सप्रेसवे पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योजना बनाकर संबंधित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए। जिसके तहत एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एन्गेजमेंट आधारित रणनीति पर निरंतर काम किया जा रहा है।

सीतारमण परिवार भी राजनैतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार को लेकर प्रभाकर की आलोचना कोई नई नहीं है। वे मौजूदा आंदोलन से पहले से ही सरकार की आलोचना करते रहे हैं। अपनी किताब "द क्रुक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया" में उन्होंने नोटबंदी सहित, सरकार के बड़े आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बेरोज़गारी को लेकर चिंता जताई है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमज़ोर होने की आशंका भी व्यक्त की है।

उन्होंने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में प्रकाश राज और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन में ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई।

सरकार के बारे में प्रभाकर के सार्वजनिक विचार हमेशा उन विचारों से अलग रहे हैं, जिनसे सीतारमण जुड़ी हुई हैं। तथापि, दोनों के राजनीतिक मतभेद नए नहीं हैं। दोनों की मुलाकात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। राजनीतिक विचार अलग होने के बावजूद, उन्होंने1986 में शादी की थी।

प्रभाकर खुद भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वे 2009 में अभिनेता चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी से जुड़े थे। इसके बाद 2014 से 2018 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार में संचार सलाहकार के रूप में काम किया। अप्रैल 2018 में, जब तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने आंध्र प्रदेश के लिए "विशेष श्रेणी का दर्जा" न मिलने के कारण, नैशनल डैमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तब प्रभाकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

प्रभाकर का राजनीतिक सफर, उनकी पत्नी के उस सफर से बिल्कुल अलग रहा है, जिसमें निर्मला सीतारमण ने भाजपा के अंदर तरक्की की और अंततः वित्त मंत्री बनीं।

प्रभाकर की भागीदारी एसआईआर विरोधी आंदोलन के राजनीतिक संदेश को और जटिल बना सकती है। वित्त मंत्री से उनके जुड़ाव के कारण, वे इस अभियान में एक प्रमुख आवाज बन सकते हैं। यह अभियान सरकार और चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहा है।

आम विपक्षी नेताओं से अलग, प्रभाकर का उस सरकार से व्यक्तिगत संबंध है, जिसकी वे आलोचना करते हैं। इस संबंध की वजह से मीडिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सकता है और लोग उनके तर्कों को सामान्य राजनीतिक पक्षपात से अलग हटकर देखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके विचार भारतीय जनता पार्टी या सरकार के भीतर किसी तरह के मतभेद को दर्शाते हैं। यह मामला सार्वजनिक पद और निजी राजनीतिक विचारों के बीच के रिश्ते को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी मंत्री के जीवनसाथी के लिए यह जरुरी नहीं है कि वह सरकार का समर्थन करे। उसी तरह जीवनसाथी द्वारा की जाने वाली राजनीतिक आलोचना के लिए उस मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सीतारमण के लिए इसका तात्कालिक राजनीतिक महत्व सरकार में उनके पद पड़ने वाले किसी स्पष्ट असर के बजाय, लोगों के सामने दिखने वाले विरोधाभास में है। जब तक कोई सबूत न मिल जाए, तब तक यह मान लेने का कोई आधार नहीं है कि प्रभाकर की भागीदारी से उनके वैवाहिक संबंधों में दरार आई है या इससे भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री की स्थिति पर कोई असर पड़ा है।

"द इंडियन एक्सप्रेस" की एक रिपोर्ट के बाद यह विवाद और तेज हो गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि ज्ञानेश कुमार ने अपने साथी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया या उन पर ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी सहित, विपक्षी नेताओं ने इस विवाद को कांग्रेस के व्यापक वोट चोरी अभियान से जोड़ने की कोशिश की है।

यह देखना अभी बाकी है कि प्रभाकर के शामिल होने से इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिलता है या नहीं। लेकिन उनकी मौजूदगी ऐसे विरोध प्रदर्शन को एक नया राजनीतिक आयाम देती है, जो पहले से ही चुनावी निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही को राष्ट्रीय बहस के केन्द्र में लाने की कोशिश कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घटना एक दिलचस्प विरोधाभास पेश करती है। उसकी वित्त मंत्री के पति उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो चुनावी लोकतंत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के रुख को चुनौती दे रहा है। वहीं, प्रभाकर की सार्वजनिक पहचान, एक ऐसे आलोचक के रूप में और मजबूत होती है, जिनके राजनीतिक विचार उनकी पत्नी से अलग हैं।

अंततः, उनके इस कदम का महत्व पारिवारिक संबंधों से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शनकारी क्या सबूत पेश करते हैं, चुनाव आयोग क्या जवाब देता है और यह अभियान अपने मौजूदा राजनीतिक दायरे से बाहर कितना जनसमर्थन जुटा पाता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार